बिग बैंक सिद्धांत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विलय पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

31 अगस्त, 2019

"विलय पर लिया गया फैसला बेहतर तरीके से कार्य करे इसके लिए कर्मचारियों से जुड़े खर्च में तालमेल को समझना महत्त्वपूर्ण है।"

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कई बैंकों के आपस में विलय का ऐलान किया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक का विलय होगा। दूसरी तरफ, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का भी आपस में विलय किया जाएगा। इसी तरह यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी विलय किया जाएगा। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का भी आपस में विलय होगा।

केंद्र सरकार के इस बड़े ऐलान के साथ ही अब देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। विलय सहक्रियाओं द्वारा संचालित होते हैं अर्थात उत्पादों, लागतों, व्यापार, भौगोलिक या प्रौद्योगिकी और सबसे महत्त्वपूर्ण, खर्च में तालमेल। हालांकि, विलय होने वाले बैंकों के बीच कुछ भौगोलिक तालमेल हो सकते हैं, लेकिन जब तक कि उन्हें शाखा और कर्मचारियों के युक्तिकरण के माध्यम से कर्मचारियों से जुड़े खर्च में तालमेल का एहसास नहीं होता है, विलय का अर्थ उनके लिए या अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक मायने नहीं रखेगा। यहीं पर सरकार की रणनीति का परीक्षण किया जाएगा।

हम सब यह जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या अधिक हैं। इसके अलावा, शाखा नेटवर्क में ओवरलैप की संभावना भी बढ़ जाती है जैसे कि केनरा-सिंडिकेट बैंक विलय, विशेष रूप से कर्नाटक में और कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों में और इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जहाँ दोनों का उत्तर और पश्चिम में मजबूत नेटवर्क है।

इसलिए, इन बैंको के विलय की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये बैंक कर्मचारी युक्तिकरण के संवेदनशील मुद्दे को कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ पहले ही इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो चुका है।

यह 1990 के दशक के अंत में नरसिम्हम समिति थी जिसने मजबूत बैंकों के विलय की प्रक्रिया के माध्यम से समेकन की सिफारिश की थी। तब से यह मुद्दा क्रमिक सरकारों के ध्यान में रहा है। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि कमजोर बैंकों को बंद कर दिया जाये और उन्हें मजबूत बैंकों के साथ विलय नहीं किया जाये जैसा कि अभी किया जा रहा है। साथ ही संसद में इसका विरोध भी नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी का भी विरोध इतने बड़े बहुमत वाली सरकार के आगे टिक नहीं सकता।

विलय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे बड़े पैमाने पर बैंकों का निर्माण करेंगे, क्योंकि वर्तमान में भारत में बहुत सारे बैंक ऐसे आकार वाले हैं जो वैश्विक मानकों के आधार पर बहुत नीचे हैं, जिनकी वृद्धि वैश्विक मानकों पर बहुत कम है।

फिर भी, विलय के बाद भी यदि इन बैंकों के शासन और प्रबंधन में पर्याप्त सुधार नहीं किया जाता तो भी ये लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए, सुश्री सीतारमण ने प्रबंधन को बोर्ड के प्रति बेहतर जवाबदेह बनाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है। लेकिन किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण सुधार बोर्ड स्तर पर होते हैं, जिसमें नियुक्तियां भी शामिल हैं, विशेष रूप से सरकारी उम्मीदवारों के लिए।

ये अक्सर राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, जिसमें बैंकिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। निश्चित रूप से, इस तरह की प्रथाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है क्योंकि वैश्विक बैंकों की परिभाषा केवल आकार के बारे में नहीं है बल्कि शासन भी पेशेवर होना चाहिए।

सरकार को एक साथ चार विलय के दुष्प्रभाव से निपटने का भी प्रबंधन करना होगा, क्योंकि यह उद्योग में उथल-पुथल का कारण बन सकता है। अगर ये विलय एक-एक करके किए गए होते तो शायद बेहतर होता।

GS World टीम...

बैंकों का विलय

चर्चा में क्यों?

- सरकार ने आर्थिक सुस्ती दूर करने और देश में विश्वस्तरीय बैंक बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की है।
- बैंकों के इस महाविलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। वर्ष 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 थी।
- इस विलय के बाद पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा।
- एसबीआई का कारोबार 52.05 लाख करोड़ रुपये का है तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय के बाद पीएनबी का कारोबार 17.95 लाख करोड़ रुपये का होगा। इसकी शाखाओं की संख्या 11,437 हो जाएगी।

बैंकों की स्थिति

- पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और युनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय होगा।
- अब इसका कुल कारोबार 18 लाख करोड़ रुपए का होगा।
- केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का विलय होने के बाद यह देश का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा। अब इस बैंक का कुल कारोबार 15.2 लाख करोड़ रुपए का होगा।
- यूनियन बैंक के साथ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय होगा।

- इस विलय के बाद यह देश का पांचवां सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा। अब इन बैंको का कुल कारोबार 14.6 लाख करोड़ रुपए का होगा।
- इसके अतिरिक्त इंडियन बैंक का विलय इलाहाबाद बैंक के साथ होगा। इस विलय के बाद यह देश का सातवां सबसे बड़ा बैंक होगा। अब इसका कुल कारोबार 8.08 लाख करोड़ रुपए का होगा।
- केंद्र सरकार के इस बड़े घोषणा के साथ ही अब देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह जाएगी।
- साथ ही विजया बैंक, देना बैंक के विलय से बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा बड़ा बैंक बन गया है। इसका कारोबार 16.13 लाख करोड़ रुपये का है।
- सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद केनरा बैंक 15.20 लाख करोड़ रुपये के कारोबार और 10,324 शाखाओं के साथ देश का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनेगा।

बैंकों के विलय की पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीयकृत बैंकों का पहला विलय वर्ष 1993-94 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू इंडिया बैंक के विलय को माना जाता है।
- इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय पर विचार करने के लिये कई समितियाँ गठित की गई- वर्ष 1998 में नरसिम्हन समिति, वर्ष 2008 में लीलाधर समिति और वर्ष 2014 में नायक समिति।
- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और दो नॉन-लिस्टेड बैंक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ-साथ भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया था।

विलय से होने वाले लाभ

- बैंकों का विलय छोटे और भारी घाटे में चल रहे बड़े बैंकों में करने से सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली मजबूत होगी।
- इससे बैंक मजबूत और टिकाऊ तो बनेंगे ही, साथ में उनकी ऋण देने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे बैंकों के बैड लोन के मुद्दे को हल करना और ऋण की बढती मांग को पूरा करना आसान हो सकेगा।
- बैंकों के विलय से इनकी संख्या तो कम होती ही है, साथ ही इन्हें बेहतर तरीके से पूंजी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- बैंकों के विलय से बैंकिंग सेवाओं का दायरा भी बढ़ जाता है और ग्राहकों को देशभर में आसानी से बैंकिंग सेवाएँ मिल जाती हैं।
- देखा यह गया है कि विलय से बैंकों की परिचालन क्षमता बढ़ती है तथा संचालन लागत में कमी आती है। इससे बैंकिंग गतिविधियों में वृद्धि तथा बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार भी होता है।

नरसिम्हन समिति

- भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा करने तथा इसमें सुधार की पहल हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया। इनमें एम. नरसिम्हन समिति सबसे महत्त्वपूर्ण है।
- एम. नरसिम्हन के नेतृत्व में दो समितियों का गठन हुआ जिन्हें क्रमशः नरसिम्हन समिति-1 (1991) और नरसिम्हन समिति-II (1998) के रूप में जाना जाता है।
- नरसिम्हन समिति की सिफारिशों ने भारत में बैंकिंग क्षमता को बढ़ने में मदद की है।
- इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये व्यापक स्वायत्तता प्रस्तावित की गई थी।
- समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के विलय के लिये भी सिफारिश की थी।
- इसी समिति ने नए निजी बैंकों को खोलने का सुझाव दिया जिसके आधार पर 1993 में सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान की।
- आरबीआई की देखरेख में बैंक के बोर्ड को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने की सलाह भी नरसिम्हन समिति ने दी थी।
- बैंकिंग-वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु प्रमुख समितियाँ
- नरसिम्हन समिति - बैंकिंग सुधार
- चेलैया समिति - कर सुधार
- रंगराजन समिति - भुगतान संतुलन
- जानकीरमन समिति - प्रतिभूति घोटाला।
- स्वामीनाथन समिति - जनसंख्या नीति
- महालनोबिस समिति - राष्ट्रीय आय
- मलहोत्रा समिति - बीमा सुधार
- भण्डारी समिति - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुधार
- सच्चर समिति - मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन
- खुसरो समिति - कृषि साख
- दामोदरन समिति ख्र बैंकिंग सेवाओं में सुधार
- गोपीनाथ समिति- राष्ट्रीय लघु बचत कोष
- नाचिकेत मोर समिति - वित्तीय समावेशन

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के विलय के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. हाल के विलय के पश्चात सरकारी बैंको की संख्या घटकर 12 हो जाएगी।
2. बैंको के विलय की सिफारिश रंगराजन समिति द्वारा किया गया था।
3. देश में विश्वस्तरीय बैंक बनाने के लिए सभी सार्वजनिक बैंको का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने का लक्ष्य रखा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 3

(c) 1 और 3

(d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements regarding merger of public sector banks.

1. After the recent merger, the number of government banks will be reduced to 12.
2. The merger of Banks was recommended by Rangarajan Committee.
3. To create a world-class bank in the country, all public banks have been targeted to merge into

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 3

(c) 1 and 3

(d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंको के विलय का निर्णय लिया है। इस विलय से उत्पन्न समस्याओं की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. Recently, the government has decided to merge several public sector banks. Discuss the problems arising out of this merger. (250Words)

नोट : 30 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।